डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, दिल्ली म चीफ कमिश्नर साहब एक्शन लेते हैं, भारत सरकार नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर चीफ़ कमिश्नर की ज़िम्मेदारी नहीं है । यहां की ज़िम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है ।

Shri A. T. Sarma: May I know whether these rules are applicable to ayurvedic drugs also?

डा० सुशीला नायर : चार पांच किस्म्म की दवायें हैं, जिन के बारे में यह कानून ज्यादा लागू होता है । अगर जादू के किस्म की दवाओं के बारे में कोई भी एडवरटाइज़मेंट करता है, तो उस को सज़ा ी जाती है । कुछ समय पहले हमदर्द दवा खाने पर भी एक केस चला था ।

Mr. Speaker: Next question

Shri A. T. Sharma: *rose*—

Mr. Speaker: Order ,order. Next question.

राज्यों में पीने का पानी

+

५२८. { **श्री बाल कृष्ण सिंह** :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री पें० वेंकटासुब्बैया : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में "शुद्ध पय जल उपलब्ध करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, ो उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में इस योजना को क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सफाई योजना १९५४ में बनाई गई थी और द्वितीय एवं तृतीय च वर्षीय योजनाओं में भी यह चलती आ रही है ।

(ख) यह कार्यक्रम किसी खास क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है । ये योजनायें राज्य के विभिन्न स्थानों में क्रियान्वित की जा रही हैं । राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के जिन स्थानों के लिए अब तक जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, उन की एक सूची सभा-पटल पर रख ी गई है । **[पुस्तकालय म रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०१०१३।६३ ।]**

श्री बाल कृष्ण सिंह : श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन स्थानों में यह योजना लागू की जा रही हैं उन स्थानों के चुनाव के लिए किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?

डा० सुशीला नायर : राज्य सरकारें किन बातों को ध्यान में रख कर चुनाव करती हैं, यह मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकती । आवश्यकता वग़ैरह को देख कर वे ऐसा करती होंगी । जो स्कीम्ज़ हमारे पास राज्य सरकारों की ओर से आती हैं, उन को टेक्निकल दृष्टि से देख कर उन के लिए यहां से सहायता दी जाती है ।

श्री बाल कृष्ण सिंह : स्टेटमेंट के पेज ४, आइटम १४ पर लिखा है, "विलेजेज़ नियर इर्रिगेशन ट्यूबवेल्ज़" । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह एक जेनरल पालिसी है कि जो गांव इर्रिगेशन ट्यूबवेल्ज़ के निकट हों, उन में यह स्कीम लागू की जाये कुछ ख़ास स्थान इस सम्बन्ध में चुने गए हैं ।

डा० सुशीला नायर : जिन जगहों पर इर्रिगेशन ट्यूबवेल का पानी मीठा और अच्छा होता है, उस को ले कर पीने के पानी का प्रबन्ध किया जा सकता है और कुछ पर किया भी गया है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ है कि उत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में पीने का शुद्ध जल बिल्कुल नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्या वहां पर अच्छा पानी उपलब्ध करने के लिए कोई विशेष योजना तयार की जा रही है ?

डा० सुशीला नायर : मैं राज्य सरकार से पूछ कर माननीय सदस्य को इन्फर्मेशन दे सकती हूं ।

Shri S. N. Chaturvedi: May I know if there is any ceiling on the expenditure on individual schemes?

Dr. Sushila Nayar: Yes, Sir. Generally speaking, the ceiling is Rs. 10,000 for a village.

Shri P. Venkatasubbaiah: May I know whether the attention of the Government has been drawn to the fact that where the schemes have been introduced most of them have become failures, the reason being that the expenditure has to be borne by the villagers? The result is that no panchayat is coming forward, and some of these water supply and sanitary schemes are proving a big failure. Has that fact been brought to the notice of the Government?

Dr. Sushila Nayar: I am not aware of this fact that they have been failures. I know that in some places where some water taps were introduced without adequate drainage, the villagers did not like it. So, we are insisting that if we put up taps, we must have the drainage facilities along with that.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या झज्जर और रेवाड़ी क्षेत्र के बारे में पंजाब राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना दी है ?

डा० सुशीला नायर : एक एक स्कीम बारे में तो इस वक्त मझे मालूम नहीं है ।

Shri Mohammad Elias: In view of the Indian Medical Association's Report with regard to West Bengal where cholera breaks out every now and then due to scarcity of drinking water, may I know whether Government is having any special scheme apart from the CMPO to supply pure drinking water in West Bengal to prevent cholera?

Dr. Sushila Nayar: There is no report from the Indian Medical Association. It was the Indian Council of Medical Research which appointed a special committee, and it has reported that South Howrah is the reservoir from which cholera spreads to other parts of India from time to time, it is an endemic area. It was in view of this that we have sanctioned huge sums to set up the special organisation of CMPO which is going into the total question of a master plan, sanitation, water supply and evrything for Calcutta.

श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्राणी यह जानती हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के कथनानुसार उस राज्य में नौ हजार ऐसे गांव हैं, जहां एक कुआं भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार के सम्पर्क में इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर: मैं तो यह नहीं कह सकती हूं कि वहां पर नौ हजार या कितने गांव हैं, जहां कुएं नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि मध्य प्रदेश में . . . .

श्री भानु प्रकाश सिंह : उन्होंने वक्तव्य दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप वह पूछ रहे हैं, जो कि इन को मालूम है। जो कुछ वहां के मंत्री महोदय को मालूम है, वह तो एक अलाहदा बात है ।

डा० सुशीला नायर : कुछ इलाके हैं जहां पर पानी की तंगी है । दूसरे कई राज्यों में भी इस प्रकार के इलाके हैं जहां पानी

की तंगी है । इन इलाकों के लिए क्या योजना बन सकती है, कहां से पानी लाया जा सकता है, उस पर क्या खर्चा होगा, क्या टैक्नीकल डिटेल्ज़ होंगी, यह सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए खास इनस्वेटीगेशन डिविज़ंज़ कायम करने की योजना बनाई गई है और कुछ जगहों पर वे चल भी रहे हैं ।

Shrimati Yashoda Reddy: May I know if there has been a substantial cut in the allotment to the Ministry in view of the emergency and whether this particular item has also been affected and if so, to what extent?

Dr. Sushila Nayar: There has been an overall cut for the coming year, that is, 1963-64, of the order of 27·5 per cent and I could not say exactly what effect it will have on the water supply schemes.

Shri Mohammad Elias: The hon. Minister has very rightly pointed out that a huge amount has been sanctioned by the Central Government to give pure water to Howrah. But not a single rupee has been sent to improve the water supply.

Mr. Speaker: Next question . . . (*Interruptions*.)

Shri Mohammad Elias: Will the Government see that the money is spent?

Mr. Speaker: He does not put a question but is arguing the case. Next question.

विदेशी मुद्रा

\+

*५२६. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :
श्री प्र० चं० बरुग्रा : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली में परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में; और

(ग) कार्य-प्रणाली में किए गए परिवर्तनों के फलस्वरूप किन-किन परियोजनाओं को पूरा करने में सुविधा मिलेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। कार्य प्रणाली को उन्नत करने के लिए पग उठाये गये हैं ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०-टी० १०१४।६३]**

(ग) सभी सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं को ।

[(a) Yes, Sir. Steps have been taken to improve the procedure.

(b) A statement is laid on the Table on the House [Placed in Library, *See* No. LT-1014|63].

(c) All Irrigation and Power Projects.]

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस विवरण को देखने से मालूम पड़ता है कि नए फारेन एक्सचेंज रूल्ज़ १ जनवरी १६६३ से लागू किये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि नए रूल्ज़ लागू करने के बाद कुल कितनी विदेशी मुद्रा रिलीज़ की गई है ?

Shri Alagesan: I have not been able to give that figure but the object of the streamlining of this procedure is to reduce the time for the clearance of projects. Formerly, it was taking about six months. As a result of the new procedure, it will not take more than two months.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं जानना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों की वजह से इस विभाग की कुल कितनी योजनाओं का काम रुका हुआ है ?

Shri Alagesan: Most of our projects have been cleared; there is no such holdup.

Shri P. C. Borooah: What is the amount of foreign exchange in